विचार बिन्दु

मनुष्य का कत्तर्व्य है कि वह उदार बनने से पहले त्यागी बने। –डिकेंस

नई पीढ़ी कटघरे में क्यों?

क्या हमारी नई पीढ़ी सचमुच ग़ैर ज़िम्मेदार है? दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए शिक्षामंत्री हटाओ आंदोलन के बाद यह प्रश्न फिर से चर्चा के केंद्र में है। असल में यह आंदोलन अनेक ऐसे प्रश्न छोड़ गया है, जिन पर लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। इस आंदोलन ने एक विरोधाभास भी सामने रखा। कुछ युवाओं की अमर्यादित अभिव्यक्तियाँ आलोचना का कारण बनीं, तो उन्हीं युवाओं का अनुशासन, साहस और संगठन-क्षमता व्यापक सराहना का विषय भी बनी। हमारा समय तीखे ध्रुवीकरण का है। ऐसे समय में किसी एक या किन्हीं कुछ घटनाओं के आधार पर किसी पीढ़ी का मूल्यांकन करना उचित नहीं कहा जाएगा।

अगर आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि दुनिया के हर देश और हर काल में वर्तमान पीढ़ी अपनी उत्तराधिकारी पीढ़ी से असंतुष्ट रही है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों और रोमन लेखकों ने युवाओं की खूब शिकायतें की हैं। असल में तो हर युग में बुज़ुर्गों ने युवाओं के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। उनकी मुख्य शिकायतें ये रही हैं कि युवा मेहनत से कतराते हैं, वे अनुशासनहीन हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके मन में परंपराओं के प्रति सम्मान नहीं है वगैरह। आजकल भारत में बड़ों से यह सुनना आम है कि युवा हर समय मोबाइल में खोये रहते हैं और कोई सार्थक काम करने की बजाय रीलें देखते रहते हैं। भारतीय बुज़ुर्गों की आम राय यह है कि वे बहुत अच्छे थे और युवा उतने अच्छे नहीं हैं। हमारे ज़माने में.... उनका बेहद प्रिय प्रारम्भिक कथन होता है। रोचक बात यह है कि हर पीढ़ी की अपनी बाद वाली पीढ़ी के लिए ऐसी ही राय रही है।

अगर हम आज की युवा पीढ़ी को देखें और उसका एक तटस्थ आकलन करने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि जो आरोप उस पर लगाए जाते हैं, वे एक सीमा तक सही भी हैं। मसलन यही कि उसमें धैर्य की कमी है। वह बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लेना चाहती है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि इसमें बुराई क्या है? जो चीज़ हमारी पीढ़ी को बीस साल में हासिल हुई उसे अगर बाद वाली पीढ़ी पांच साल में हासिल करना चाहती है और कर भी रही है, तो इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, न कि आलोचना। इस पीढ़ी पर आरोप लगाया जाता है कि इसे संस्थाओं पर, चाहे वे सामाजिक हों, धार्मिक हों, सांस्थानिक हों, प्रशासनिक हों, कोई भी हों- कम भरोसा है। बात सही है। लेकिन विचार कीजिए कि क्या संस्थाओं ने ख़ुद को ऐसा बनाया है कि उन पर आँख मूंदकर भरोसा किया जाए? अगर नहीं, तो उन पर कम भरोसा रखना कौन-सा गुनाह हो गया? नई पीढ़ी की डिजिटल निर्भरता की बहुत आलोचना होती है। ठंडे मन से सोचिए, क्या इससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि नहीं हुई है? कब तक हम केवल परंपरा के नाम पर नवाचारों से कतराते रहेंगे?

इसी संभावनाशील युवा पीढ़ी का एक हिस्सा ग़ैर ज़िम्मेदार, अराजक, और उच्छृंखल भी है। उसमें त्वरित सफलता की इतनी तीव्र आकांक्षा है कि असफलता का सामना करने का धैर्य जैसे रह ही नहीं गया है। सोशल मीडिया ने तुलना और त्वरित मान्यता की ऐसी संस्कृति बना दी है कि उसके अभ्यस्तों को संघर्ष की लम्बी यात्रा असहनीय लगने लगती है। बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो अपने आसपास के यथार्थ से एकदम निर्लिप्त हैं और उनका एकमात्र सरोकार अपना पैकेज है। ऐसे भी युवा हैं जिनके लिए नैतिकता अब कोई मूल्य नहीं है। लेकिन पूरी युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व ऐसे युवा नहीं करते हैं।

पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दों पर युवा पीढ़ी ने जो सक्रियता दिखाई है वह हम सबको आह्लादित करती है। भारत में भी समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर इसी पीढ़ी ने ख़तरे उठाकर भी अपनी आवाज़ बहरे कानों तक पहुंचाई है और वर्तमान नीट परीक्षा वाले आंदोलन में युवाओं ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है।

अधिकांश युवा ऊर्जा और उत्साह से लबरेज़ हैं। उनकी गहरी संलग्नता अपने परिवेश और समय के साथ है और इस बात के प्रमाण वे समय-समय पर देते भी रहते हैं।

अब ज़रा तस्वीर का यह पक्ष भी ठीक से देख लिया जाए। पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दों पर युवा पीढ़ी ने जो सक्रियता दिखाई है वह हम सबको आह्लादित करती है। भारत में भी समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर इसी पीढ़ी ने ख़तरे उठाकर भी अपनी आवाज़ बहरे कानों तक पहुंचाई है। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन, जेपी आंदोलन, अन्ना के आंदोलन और वर्तमान नीट परीक्षा वाले आंदोलन में युवाओं ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। नीट वाले आंदोलन में अनुशासन का बने रहना, लड़कियों के प्रति दुर्व्यवहार का एक भी मामला न होना, सत्ता की निरंकुशता का सामना उत्कृष्ट हास्यबोध और रचनात्मकता से करना, और पूरे आंदोलन स्थल को यथासंभव साफ़ रखना ऐसे बिंदु हैं जिन्हें सर्वत्र सराहा गया है। और ऐसा नहीं है कि यह पीढ़ी केवल आंदोलनों में ही अपनी क्षमता प्रदर्शित करती है। भारत की स्टार्टअप संस्कृति, तकनीकी नवाचार, ओपन-सोर्स समुदाय, स्वयंसेवा, रक्तदान और आपदा-राहत जैसे असंख्य क्षेत्रों में उसकी ऊर्जा और रचनात्मकता साफ दिखाई देती है। कला संस्कृति के क्षेत्र में भी इनका योगदान उल्लेखनीय और सराहनीय है।

यहीं ज़रा ठहर कर ख़ुद से एक सवाल कर लिया जाना चाहिए। हम युवा पीढ़ी का आकलन करते हैं, इस पीढ़ी को अक्षम, अकर्मण्य, आलसी, ग़ैर ज़िम्मेदार वगैरह ठहराते हैं। उस पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या हम इन्हें ज़िम्मेदारी भी देते हैं? क्या हम इन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ करने की आज़ादी भी देते हैं? घर-परिवार में, शैक्षिक संस्थाओं में, समाज में, राजनीति में-कहां हम इन्हें खुलकर कुछ करने देते हैं? राजनीति में वृद्धजन युवाओं के लिए जगह खाली ही नहीं करते हैं। घर-परिवार में कोई किशोर या युवा क्या पढ़ेगा, यह उसके बजाय उसके मां-बाप तय करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अपनी पसंद से विवाह करना चाहे तो उसे सुनना पड़ता है, क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? आजीविका के मामले में हम कभी उसे स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते। अगर वह किसी कला या खेल में रुचि लेता है तो हम उसे धिक्कारते हैं और पढ़ाई में मन लगाने के लिए धकेलते हैं। वह गायक बनना चाहता है हम उसे आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा भेज देते हैं। ज़रा सोचिये, जिस देश और समाज में बीस-पच्चीस साल के युवा की ज़िंदगी के सारे फैसले उसके पचास-साठ साल के माता-पिता ही करें, वहां युवाओं से किस ज़िम्मेदारी की अपेक्षा की सकती है? और क्यों की जानी चाहिए? हम उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने-फिरने तो देते नहीं और फिर कहते हैं कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है।

इतना सब कह देने के बाद यह भी कहना ज़रूरी है कि हर पीढ़ी अपना निर्माण ख़ुद करती है। वह अपनी राह और मंज़िल खुद चुनती है, बशर्ते उसे ऐसा करने दिया जाए। हमारा स्वभाव यह है कि हम अपनी बाद वाली पीढ़ी के हाथ पांव बांध कर उस पर आरोप लगाने में सुख प्राप्त करते हैं कि वह दौड़ नहीं रही है। हम उससे ज़िम्मेदारी की अपेक्षा तो करते हैं लेकिन उसे ज़िम्मेदारी सौंपने की हिम्मत नहीं दिखाते। हम उसके लिए रास्ते तय करते हैं, उसकी मंज़िल निश्चित करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो रही है। सच तो यह है कि हर पीढ़ी अपने से बाद वाली पीढ़ी को वही देती है जो उसके भीतर होता है - विश्वास या भय। यदि हम सक्षम युवाओं का समाज चाहते हैं तो उन्हें नियंत्रित करने से अधिक उन पर विश्वास करना सीखना होगा।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

राशिफल सोमवार 3 अगस्त, 2026

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2083, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 तक, सुकर्मा योग रात्रि 9:14 तक, कौलव करण दिन 11:03 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मिथुन, बुध-मिथुन, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज प्रथम सावन वन सोमवार, नाग पंचमी (राज.) है। आज हरदेव पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:35 तक, शुभ 9:14 से 10:54 तक, चर 2:12 से 3:51 तक, लाभ-अमृत 3:51 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 7:10

मेष

घर-परिवार के कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। समय अनावश्यक खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

सिंह

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय बना रहेगा। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

धनु

घर-परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

वृष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

कन्या

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी और महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

तुला

नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आय में वृद्धि होगी।

कुंभ

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कर्क

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

वृश्चिक

परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आज अनाश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मीन

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित योजना बनेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का मानसिक तनाव दूर होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाने का सच - आधी हकीकत, आधा फ़साना

रामपाल जाट

दोहरे मापदंड:- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री सुरेश गोपी द्वारा लोकसभा में 7 अगस्त 2025 को दिए गए उत्तर के अनुसार 2014-15 से जून 2025 तक इथेनॉल मिश्रण से 238 लाख मैट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ, एवं 1,40,000 करोड रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। भारत के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार इसी अवधि में खाद्य तेल एवं दलहन के आयात की मात्रा 1,311.6 मैट्रिक लाख टन रही एवं आयात पर 21,09,600 करोड रुपए खर्च हुए हैं, यानि यह बचत की राशि से 15 गुणा से अधिक है। सुदृढ़ खाद्य सुरक्षा एवं इथेनॉल निर्माण में से प्राथमिकता का निर्धारण किए बिना ही दीवार घड़ी के पेंडुलम की भांति चलना दोहरे मापदंडों का परिचायक है।

भारत में वर्ष 2003 मे पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय नीति आरंभ हुई। वर्ष 2014 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा 1.5 प्रतिशत रही, वर्ष 2014 जून के बाद मिश्रण की मात्रा 5 से 10 प्रतिशत कर दी गई, 2018 में नई नीति तैयार की गई, जिसके अनुसार मिश्रण की मात्रा को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की अवधि 2030 निर्धारित की गई, इसके 5 वर्ष पूर्व मार्च 2025 में मिश्रण की मात्रा 19.2 प्रतिशत कर दी गई, जो 2025-26 में 20 प्रतिशत हो गई। इस नीति में ब्राजील की भांति गाड़ियों के अनुकूल इंजन तैयार करने, मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने, और जनसामान्य को विकल्प देने का प्रावधान नहीं किया गया।

राजनेताओं की चीनी मिलों को घाटे से बचाने के लिए इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की नीति पर वर्ष 2013 के पहले विचार आरंभ हो गया था। माह जून 2014 के उपरांत सरकारी प्रभाव से इस नीति के पंख लग गए। इसी को न्यायोचित ठहराने के लिए अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाकर मालामाल करने का राग अलापना आरंभ हो गया।

देश में प्रदूषण रहित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत जानवर था, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के नाम पर पार्श्व में धकेल दिया गया। ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों की अपेक्षा इथेनॉल को रामबाण औषधि के रूप में मान लिया गया। इसी से इथेनॉल निर्माण इकाइयों को मूल्य निर्धारण एवं विपणन की चिंता से मुक्त कर दिया गया। उन पर संरक्षण एवं सहायता के रूप में सरकारी कृपा बरसना आरंभ हो गई। इथेनॉल से अपेक्षित अच्छे विकल्पों के विचार पर ग्रहण लग गया। राजनीति में स्वयं को लूट से दूर रखने का संकल्प व्यक्त करने वाले भी ऐसे परिवेश में लूट की धारा में बह जाते हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होने लगती है। लालच को त्यागे बिना स्वयं की श्रेष्ठता को प्रमाणित करने में वे अपनी बुद्धि एवं शक्ति का उपयोग करने लग जाते हैं। यह कागज के फूलों में सुगंध उत्पन्न करने जैसा ही निरर्थक श्रम है।

जिस मक्का की इथेनॉल निर्माण में 72 प्रतिशत भागीदारी रही है, उस मक्का को 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' 2400 रुपए प्रति क्विंटल होते हुए भी मक्का उत्पादक किसानों को एक क्विंटल के दाम अधिकतम 1800 रुपये प्राप्त हुए। जबकि इथेनॉल निर्माण इकाइयों ने उत्पादन खर्च की गणना 2400 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर की थी, उसी के अनुसार इथेनॉल निर्माण इकाइयों को एक लीटर इथेनॉल के दाम 71.86 रूपये प्राप्त हुए। किसानों को प्राप्त होने वाले अधिकतम दामों के आधार पर गणना करने पर एक लीटर के दाम 54.52 रुपए प्राप्त होने चाहिए थे। इसी प्रकार 100 प्रतिशत कटे चावलों की स्थिति है। जिसका घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपए प्रति क्विंटल है, इथेनॉल निर्माण इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत कटे चावल का मूल्य 2320 से लेकर 2390 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। एक नवंबर 2026 से 31 प्रतिशत अक्टूबर 2027 तक 72 लाख मैट्रिक टन चावल इथेनॉल कंपनियों के लिए आरक्षित किया गया है, इसके पूर्व 2025-26 में इसी अवधि में 52 लाख मैट्रिक टन चावल आरक्षित किया गया था। नीति आयोग तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, रोड मैप फार एथेनॉल ब्लेडिंग इन इंडिया 2020-25 के प्रतिवेदन के अनुसार गन्ने से एक लीटर इथेनॉल तैयार करने में 3000 लीटर पानी का उपयोग होता है। मेरी विरासत में कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहित कर रही है, दूसरी ओर रोडमेप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया की ओर दौड़ रही है।

विकल्प- यह सही है कि 85 प्रतिशत क्रूड विदेशों से आयात हो रहा है, होर्मुज़ बंद जैसी घटनाओं के बाद आयात की निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा को बचाना तथा पर्यावरण की रक्षा करना सामयिक आवश्यकता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, भूगर्भ से ऊर्जा, जानवरों से प्राप्त ऊर्जा जैसे श्रेष्ठतर विकल्पों के उपयोग पर विचार किए बिना देश की खाद्य सुरक्षा की बलि देना उचित नहीं हो सकता।

जिस प्रकार इथेनॉल निर्माण इकाइयों के लिए निश्चित मूल्य प्रदान करने एवं विपणन की चिंता से मुक्त रखने की नीति तैयार की गई है, इस प्रकार की नीति इथेनॉल निर्माण में काम आने वाले मक्का, चावल जैसी कृषि उपजों के लिए नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गन्ना को आवश्यक वस्तु घोषित कर गन्ना नियंत्रण आदेश प्रसारित किया गया है, उस प्रकार से मक्का को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। इसके अभाव में भी मक्का उत्पादक किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी वंचित रहना पड़ता है।

कृषि उपजों को लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून श्रेष्ठ उपाय है। सरकारी नीतियां उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं की गई है। बल्कि वर्ष 1968 में कृषि मूल्य नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटीड मूल्य के रूप में वर्णन किया गया, उसका क्रियान्वयन 58 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी नहीं हो पाया है। इसी अनुक्रम में 12 जुलाई 2022 को गठित समिति के उपसमूह ने 21 अप्रैल 2023 को न्यूनतम समर्थन मूल्य को आरक्षित मूल्य श्रेणी में रखकर मंडियों में नीलामी बोली का आरंभ न्यूनतम समर्थन मूल्य से करने संबंधी अनुशंसा की हुई है। उस समिति का प्रतिवेदन अभी तक भी प्रकाशित नहीं किया गया है। सरकार द्वारा अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का मंतव्य किसानों का कल्याण करना नहीं बल्कि किसानों के नाम पर इथेनॉल निर्माण करने वाले धनपतियों को लाभान्वित करना है। इथेनॉल को आइसोब्यूटेनॉल में बदलकर ही डीजल में उपयोग किया जा सकता है। अब भारत में डीजल में भी 15 प्रतिशत आइसोब्यूटेनॉल मिलावट करने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर भारत 1.5 करोड़ टन का पेट्रोल का फ्रांस, नीदरलैंड सहित अनेक देशों को निर्यात करता है, उसमें इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल नहीं है वरन शुद्ध पेट्रोल है। यदि मिश्रण श्रेष्ठ है तो निर्यात में भी भारत सरकार बढ़त लेनी चाहिए।

एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग करने के लिए वाहनों के इंजन के प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना पूर्ववर्ती शर्त है। ब्राज़ील ने 10 से 30 प्रतिशत की यात्रा पूरी करने में 50 वर्ष का समय लगाया, भारत में 5 से 20 प्रतिशत तक की यात्रा 6 वर्ष में ही पूरी कर ली। परिवहन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में विक्रय किए गए 10 में से 7 वाहन 80:20 मिश्रण के अनुकूल नहीं थे, कारों और दो पहिया वाहनों में 3 प्रतिशत से भी कम वाहन इस मिश्रण के अनुकूल थे। मंत्रालय के वाहन पोर्टल के अनुसार 2025 के पूर्व विक्रय किए गए 1.37 करोड़ दोपहिया वाहनों में से 52 लाख तथा 33.6 लाख कारों में से 9 लाख कार ही इस मिश्रण के अनुकूल है। इसी प्रकार दो पहिया वाहनों में 72.5 प्रतिशत, तीन पहिया वाहनों में 71.6 प्रतिशत, कारों में 72.2 प्रतिशत, हल्के मालवाहक वाहनो में 66.6 प्रतिशत इस मिश्रण के अनुकूल नहीं है। वर्ष 2023 से पहले निर्मित वाहनों में से तो कार एवं दोपहिया कोई भी एथेनॉल मिश्रण के अनुकूल नहीं है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में स्वीकार किया है कि सरकार ने इस तथ्य का आकलन नहीं कराया कि देश में कितनी प्रतिशत गाड़ियां 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के अनुकूल है। इसके बिना ही 20 प्रतिशत मिश्रण से गाड़ियों के इंजन को क्षति के संबंध में आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं होना दर्शाया है। यद्यपि इस उत्तर में 3 से 5 प्रतिशत माइलेज कम होने को स्वीकारा है। सरकार द्वारा अपुष्ट तथ्यों के आधार पर 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण को सही की संज्ञा देने से सरकार की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाती है।

वर्ष भर भारत में 300 से अधिक दिनों तक सूर्य की असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। 120 से अधिक देशों के समूह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत नेतृत्व कर रहा है। वर्ष 2025 में नयी सौर को जोड़कर 38 गीगावाट सौर क्षमता हो गई, जो अमेरिका के 35 गीगावाट से अधिक है। इस प्रकार देश की कुल सौर क्षमता 150 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है। पेट्रोल डीजल से चलने वाले उपकरणों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने से 10 करोड़ बैरल तेल की मात्रा घट सकती है, जिससे लगभग 716 अरब से 1,050 अरब रूपये विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। सौर से प्राप्त अनंत ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए विकल्प ही नहीं सामयिक राष्ट्रीय आवश्यकता है। प्रत्येक छत पर सौर उपकरणों की स्थापना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में छोटा किंतु निर्णायक कदम हो सकता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने का श्रेष्ठ उपाय है,यह होर्मोज जलडमरूमध्य की निर्भरता से छुटकारा दिलाने की दिशा में कारगर सिद्ध हो सकता है। वर्ष 2025 में 2.3 टेरावाट घंटे की सौर ऊर्जा को ग्रिड की क्षमता के अभाव में छोड़ना पड़ा था, जिसे जिसे केंद्र सरकार ने संसद में स्वीकार किया है, उसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के मध्य 8,133 गीगावॉट घंटा जीडब्ल्यूएच शोर बिजली का उत्पादन रोकना पड़ा, सबसे अधिक कटौती मई महीने में 3,235 जीडब्ल्यूएच में हुई, ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन रोकने की यह स्थिति सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा करती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर ऊर्जा क्षेत्र में छलांग लगाने की क्षमता का तदानुकूल पूरे मन से उपयोग नहीं करने का स्पष्टीकरण सरकार से अपेक्षित है। परंपरागत रूप से पशुधन का ऊर्जा के रूप में उपयोग तो अनुभव सिद्ध प्रमाण है। 'जन -जंगल- जमीन -जानवर' आधारित सर्वसुलभ- प्रदूषण रहित ढांचे को युगानुकुल तैयार करने में आधुनिकता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है।

देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन के अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वरीयता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने,भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देश की अनिवार्य आवश्यकता है। देश को समृद्ध बनाने वाले 'जन- जमीन- जंगल- जानवर' आधारित अर्थ रचना में प्रदूषण की संभावनाएं नगण्य है, वहीं पशुधन देश में ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत रहा है, जिसकी उपयोगिता प्रदूषण रहित सर्व सुलभता के रूप में पूर्व से ही सिद्ध है। इथेनॉल मिश्रण के संबंध में उल्लिखित सभी कारक वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों से प्राप्त होना संभव है।

–रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष
किसान महापंचायत।

लंदन डायरी : ब्रिटेन में सघन हरियाली का राज

पेड़ों का पृथ्वी पर बहुत महत्व है। इनके बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया के जंगलों में प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण को बनाए रखने में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रिटेन हरियाली के लिहाज से एक समृद्ध देश है। मौसम की अनुकूलता और नागरिकों का पर्यावरण के प्रति असीम प्रेम और लगाव मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अपनी इसी खूबसूरती के कारण सम्पूर्ण ब्रिटेन दुनियां भर में प्रसिद्ध है। यहां हर घर के पास 10 मिनट वाक पर एक पार्क मिल ही जायेगा। ब्रिटेन को ठीन एन्ड प्लीजेंट लैंड यूं ही नहीं कहा जाता है। यहां हरियाली सिर्फ एक नज़ारा नहीं अपितु यहाँ के निवासियों की लाइफ स्टाइल है। यहां के स्कूलों में बच्चों को छोटी उम्र से ही गार्डनिंग सिखाई जाती है। चूँकि यहां सालभर बारिश होती है, इसलिए भी घास हरी मिलती है। ब्रिटेन ने साबित कर दिया है कि इस देश में विकास के साथ नेचर को भी बचाया जा सकता है। शहरों के चारों तरफ निर्माण कार्य प्रतिबंधित है ताकि खेत खलिहान और जंगल बचे रहे। इसलिए यहाँ आकर देशी और विदेशी पर्यटकों को लगता है कि शहर भी सांस ले रहा है। ब्रिटेन में किसी भी पेड़ को काटने से पहले कॉउंसिल से इज़ाज़त लेनी पड़ती है। इस प्रदेश में हज़ारों साल पुराने पेड़ देखने को मिल जाते है। ब्रिटेन में 400 साल से भी ज्यादा पुराने जंगलों की संख्या दो हज़ार से ज्यादा है। इनकी समुचित देखभाल सरकारी और निजी ट्रस्टों के माध्यम से की जाती है। अनेक जंगलों में भ्रमण के लिए जाने पर बाकायदा प्रवेश शुल्क भी देना पड़ता है। यहाँ हर साल द वुडलैंड ट्रस्ट नये पेड़ लगाता है। ब्रिटेन में हर आदमी के हिस्से औसतन 145 पेड़ आते है।

ब्रिटेन में वृक्षारोपण का तरीका बड़ा अजब गजब है। सघन वृक्षारोपण में पौधा लकड़ी के सहारे खड़ा करते है। थोड़ा बड़ा पौधा लगाते है तो लकड़ी के दो सहारों के साथ लगाते है ताकि वह मजबूती से खड़ा रहे। मौसम तो इनका साथ बखूबी देता ही है जिससे पेड़ जिंदा रहता है। इन पंक्तियों के लेखक ने लंदन में सड़क किनारे और वहां के गांवो में इस प्रकार के हजारों पौधे देखे जो लकड़ी के सहारे खड़े थे। वृक्षों की कटाई और लकड़ी का यहाँ बड़ा कारोबार है मगर एक वृक्ष काटेंगे तो दो पहले लगा कर उसे जीवित रखेंगे। तभी यहाँ इतनी सघन हरियाली है जो तन और मन की सुकून देती है।

बाल मुकुन्द ओझा
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार।

भ्रष्टाचार का दलदल : क्या नैतिक नेतृत्व का संकट लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है?

राम शर्मा

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके प्राकृतिक संसाधनों, सैन्य सामर्थ्य या आर्थिक विकास में नहीं, बल्कि उसके सार्वजनिक जीवन की नैतिकता में निहित होती है। जब शासन व्यवस्था में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर होने लगती है, तब लोकतंत्र का बाहरी ढांचा भले ही कायम रहे, उसकी आत्मा धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है। आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यही है कि भ्रष्टाचार केवल कुछ व्यक्तियों का अपराध नहीं रह गया है, बल्कि कई क्षेत्रों में यह एक ऐसी प्रवृत्ति बन चुका है जिसने व्यवस्था पर जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुँचाई है।

देश में समय-समय पर सामने आए विभिन्न घोटाले, रिश्वतखोरी के मामले, सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप, अवैध खनन, भूमि घोटाले और भर्ती परीक्षाओं में धांधली जैसे प्रकरण यह संकेत देते हैं कि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक संकट भी है। यही कारण है कि आम नागरिक के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुका है?

भारत ने डिजिटल शासन, ऑनलाइन सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और ई-टेंडरिंग जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार कम करने के अनेक प्रयास किए हैं। इन सुधारों का सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है। फिर भी अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) 2025 में भारत 182 देशों में 91वें स्थान पर रहा। यह स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बेहतर अवश्य है, किंतु यह भी संकेत देती है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है।

भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह गरीब और ईमानदार नागरिक को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है। जब किसी पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार रिश्वत दिए बिना नहीं मिलता, जब सरकारी योजनाओं का लाभ बीच में ही कहीं गायब हो जाता है, जब योग्य अभ्यर्थी की जगह धन या प्रभाव रखने वाला व्यक्ति अवसर प्राप्त कर लेता है, तब केवल एक व्यक्ति नहीं हारता, बल्कि पूरा लोकतंत्र कमजोर होता है। इससे युवाओं में यह संदेश जाता है कि सफलता का मार्ग परिश्रम नहीं, बल्कि पहुँच और पैसे से होकर गुजरता है। यह सोच किसी भी सभ्य समाज के लिए अत्यंत खतरनाक है।

महात्मा गांधी ने कहा था, "साधनों की पवित्रता के बिना साध्य की पवित्रता संभव नहीं।" यह विचार आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यदि शासन का उद्देश्य जनकल्याण है, तो उस तक पहुँचने के साधन भी पूर्णतः नैतिक और पारदर्शी होने चाहिए। दुर्भाग्य से आज अनेक अवसरों पर राजनीति में सेवा की भावना के स्थान पर सत्ता को विशेषाधिकार मानने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। दूसरी ओर नौकरशाही के कुछ हिस्सों में भी जनसेवा की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देने के आरोप सामने आते रहते हैं। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि देश में अनेक ईमानदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी आज भी पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के कारण व्यवस्था चल रही है। भ्रष्टाचार का एक गंभीर आर्थिक पक्ष भी है। जब सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है, तब सड़कें घटिया बनती हैं, अस्पतालों में संसाधनों की कमी रहती है, विद्यालयों की गुणवत्ता गिरती है और विकास परियोजनाएँ समय पर पूरी नहीं हो पातीं। इसका सीधा प्रभाव निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास पर पड़ता है। अंततः इसकी कीमत सामान्य करदाता को चुकानी पड़ती है। आज आवश्यकता केवल भ्रष्टाचार विरोधी भाषणों की नहीं, बल्कि संस्थागत सुधारों की है। लोकसेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो, सरकारी खरीद और ठेकों की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बने, शिकायतकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स को प्रभावी सुरक्षा मिले, न्यायिक प्रक्रिया तेज हो तथा दोषियों को समयबद्ध दंड मिले। साथ ही राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता और चुनावी सुधारों पर भी गंभीरता से कार्य करना होगा। जब तक राजनीति और प्रशासन दोनों में उत्तरदायित्व की संस्कृति विकसित नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान अधूरा रहेगा।

नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि समाज स्वयं छोटे-छोटे लाभ के लिए नियमों को तोड़ने, अनुचित सिफारिश कराने या रिश्वत देकर काम कराने को सामान्य मान ले, तो भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी होती जाती हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष सरकार और न्यायालयों के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक का भी दायित्व है। भारत आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि इस विकास यात्रा को स्थायी और न्यायपूर्ण बनाना है, तो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को सर्वोच्च मूल्य बनाना होगा। आर्थिक प्रगति तभी सार्थक होगी जब उसके साथ नैतिक प्रगति भी जुड़ी हो। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतने में निहित है।

भ्रष्टाचार का अंत केवल नए कानूनों से नहीं होगा; उसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक पारदर्शिता, त्वरित न्याय, सक्रिय नागरिक समाज और नैतिक शिक्षा-इन पाँचों का समन्वय आवश्यक है। जिस दिन सार्वजनिक जीवन में पद को अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व माना जाने लगेगा, उसी दिन भारत भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलकर सुशासन की नई पहचान स्थापित कर सकेगा। तभी 'विकसित भारत' का सपना वास्तव में जनविश्वास और नैतिकता की मजबूत नींव पर खड़ा होगा।

–राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार